

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

गालीबाज मासूम को फिर 'मंच'

डीएवी कालेज प्रकरण में एफआईआर के बाद यूपीएल फाइनल में प्रस्तुति का फैसला

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में मंच की मर्यादा और स्थानीय कलाकारों के सम्मान को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। अप्रैल में देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में मंच से कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवादों में आए हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को अब उत्तराखंड प्रीमियर लीग के ग्रैंड फिनाले में दोबारा प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले समापन समारोह में मासूम शर्मा की प्रस्तुति प्रस्तावित है।

मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि डीएवी पीजी कालेज के अप्रैल के कार्यक्रम में कथित आपत्तिजनक भाषा के मामले में डालनवाला कोतवाली में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और गायक को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भी जारी किया था। बाद में



◆ सवालियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्राथमिकता, स्थानीय कलाकारों का फिर तिरस्कार

◆ उत्तराखंड में स्थानीय कलाकारों के सम्मान को लेकर छिड़ गई एक बार फिर से बहस

शर्मा ने अपने व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से खेद जताया था। अब सवाल यह है कि जब उसी प्रकरण की गूंज अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी, तो प्रदेश के इतने बड़े सार्वजनिक आयोजन के लिए उन्हीं कलाकार का चयन कैसे हुआ? कांग्रेस समेत विभिन्न संगठनों ने आयोजन समिति और सरकार से इस चयन की प्रक्रिया तथा पूर्व विवाद की समीक्षा को लेकर सवाल किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी पूछा कि विवाद के बावजूद यूपीएल फाइनल में उन्हें मंच देने का निर्णय क्यों लिया गया और क्या कलाकारों के चयन को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश है।

विवाद का दूसरा पहलू उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों से जुड़ा है। गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार की समृद्ध लोकसंगीत परंपरा के साथ प्रदेश में नई पीढ़ी के अनेक गायक, वादक और संगीत समूह लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रदेश के बड़े सार्वजनिक मंचों पर स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता कितनी मिल रही है। मूल निवास और भू-कानून संघर्ष समिति ने भी यही मुद्दा उठाते हुए कहा कि उसका विरोध किसी बाहरी कलाकार से नहीं, बल्कि मंच पर अश्लीलता, गाली-गलौज और आपत्तिजनक भाषा से है। समिति ने सीएयू

के साथ बातचीत में भविष्य के आयोजनों में उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने की शर्त रखी।

कार्यक्रम को लेकर विरोध के बीच क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड की ओर से बताया गया कि कलाकार को कार्यक्रम का आधा भुगतान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए इस समय कार्यक्रम रद्द करना संभव नहीं है। बातचीत के बाद यह सहमति बनी कि मासूम शर्मा मंच से उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे और भविष्य में आपत्तिजनक भाषा अथवा फूहड़ प्रस्तुति नहीं करने की बात स्पष्ट करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने हालांकि कार्यक्रम रद्द कर स्थानीय कलाकारों को अवसर देने की मांग की है। दल ने कार्यक्रम रद्द नहीं होने की स्थिति में स्टेडियम के बाहर विरोध की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की बात कही है।

पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड के बड़े मंचों पर कलाकारों के चयन का कोई सांस्कृतिक

और सामाजिक मानदंड होना चाहिए? कलाकार किसी भी प्रदेश का हो सकता है और देशभर के कलाकारों का उत्तराखंड में स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन स्थानीय प्रतिभाओं को लगातार हाशिये पर रखकर बाहरी कलाकारों को प्राथमिकता देने की शिकायत लंबे समय से सामने आती रही है।

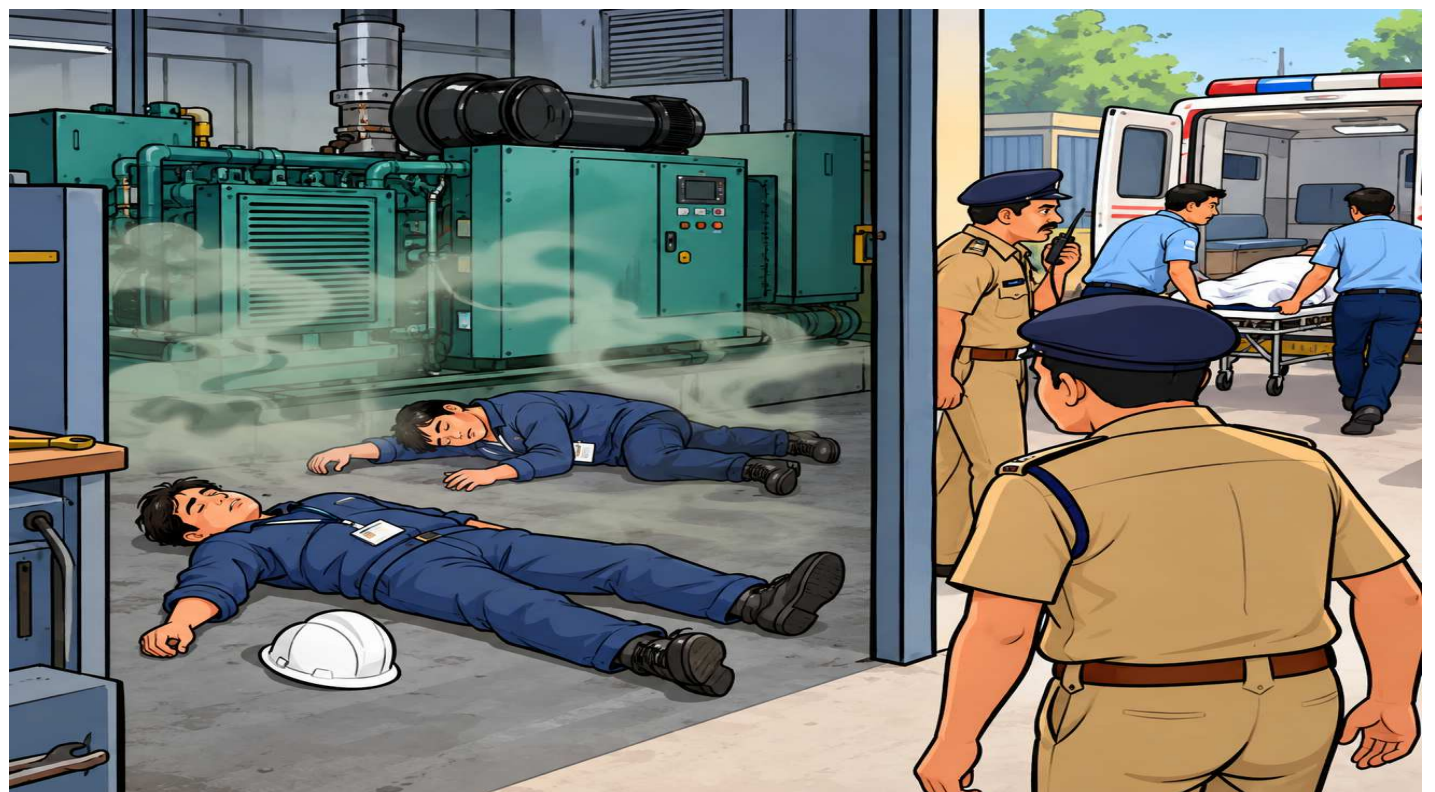
देवभूमि की पहचान केवल पर्यटन और क्रिकेट तक सीमित नहीं है। यहां की पहचान उसकी लोकभाषाओं, लोकधुनों, परंपराओं और उन कलाकारों से भी बनती है, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद पहाड़ की संस्कृति को देश-दुनिया तक पहुंचाया है। इसलिए सवाल मासूम शर्मा के कार्यक्रम से आगे बढ़कर उत्तराखंड की सांस्कृतिक नीति और आयोजकों की प्राथमिकताओं का भी है। बड़े मंचों पर बाहर से आने वाले कलाकारों का स्वागत हो, लेकिन क्या उसी मंच पर पहाड़ की अपनी आवाज को भी उतनी ही जगह मिलेगी? यह सवाल अब उत्तराखंड के कलाकारों और सांस्कृतिक जगत के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

ट्रांसपोर्ट नगर में दो इंजीनियरों की सदृग्ध मौत!

हमारे संवाददाता

देहरादून। ट्रांसपोर्ट नगर में जनरेटर रूम के अंदर दो इंजीनियरों के बेहोश मिलने से हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के जनरेटर रूम में दोनों अचेत अवस्था में मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया जनरेटर से निकली गैस के कारण दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है।

मृतकों की पहचान 29 वर्षीय रोहित सिंह निवासी हरिद्वार और 26 वर्षीय लवकुश पुत्र रामसागर निवासी फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। दोनों सिंधु सेंटर स्थित ईशान नेट सोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और इंटरनेट मेंटेनेंस का काम देखते थे। पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात करीब 12:30 बजे कंपनी में तकनीकी समस्या सामने आई थी। इसके बाद दोनों इंजीनियर समस्या की जांच करने के लिए जनरेटर रूम में गए थे। सुबह गार्ड ने दोनों को कमरे के अंदर अचेत अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पटेल नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटेल नगर कोतवाली प्रभारी



नरेश राठौर ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव

परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में जनरेटर से निकली गैस के कारण दम घुटने की आशंका सामने आई है। हालांकि,

मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

दून वैली मेल

संपादकीय

पहली तारीख और जनता की जेब

महीने की पहली तारीख अब कैलेंडर का एक साधारण पन्ना नहीं रह गई है। यह वह तारीख बन गई है, जब आम आदमी को अक्सर अपने बजट का नया हिसाब लगाना पड़ता है। कौन-सा शुल्क बढ़ा, कौन-सी शर्त बदली, किस सेवा की कीमत बदली और किस नियम का असर सीधे जेब पर पड़ेगा। हर महीने की शुरुआत इन सवालों के साथ होती है। नियम बदलना शासन की सामान्य प्रक्रिया है। बदलती अर्थव्यवस्था और नई परिस्थितियों के अनुरूप नियमों में संशोधन जरूरी भी है। लेकिन सवाल यह है कि बदलाव का बोझ सबसे पहले और सबसे ज्यादा उसी नागरिक पर क्यों दिखाई देता है, जिसकी आय बढ़ने की रफ्तार अक्सर खर्चों से पीछे रह जाती है? सरकारें सुधार के नाम पर नए प्रावधान लाती हैं और संस्थाएं अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से शुल्क तथा प्रक्रियाएं बदलती हैं। लेकिन इन फैसलों की भाषा और प्रक्रिया अक्सर इतनी जटिल होती है कि सामान्य नागरिक को यह समझने के लिए भी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ जाए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। यह कैसी पारदर्शिता है, जिसमें सूचना तो सार्वजनिक है, लेकिन समझ आम आदमी की पहुंच से बाहर? मसलन, किसी बैंकिंग सेवा का शुल्क थोड़ा बढ़ा। किसी बीमा की शर्त बदली। किसी वित्तीय सेवा पर नया प्रावधान लागू हुआ। अलग-अलग देखें तो यह परिवर्तन छोटे लग सकते हैं। लेकिन महीने-दर-महीने ऐसे बदलावों की परतें जुड़ती जाएं तो साल के अंत में यही छोटी रकम परिवार के बजट पर बड़ा असर डालती है। महंगाई केवल बाजार में कीमत बढ़ने का नाम नहीं, छोटे-छोटे शुल्कों का लगातार बढ़ना भी घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव है। विडंबना देखिए कि नीतियां बनाने वाली व्यवस्था के पास आंकड़ों की पूरी दुनिया है, लेकिन जिस व्यक्ति की जेब पर फैसेला लागू होता है, उसके लिए कोई सरल हिसाब नहीं। उसे खुद पता लगाना पड़ता है कि नए नियम से कितना फर्क पड़ेगा। क्या यह जिम्मेदारी सरकार और नियामक संस्थाओं की नहीं होनी चाहिए कि वे बदलाव की जानकारी के साथ उसका संभावित आर्थिक प्रभाव भी स्पष्ट करें? और यहीं से जवाबदेही का सवाल उठता है। किसी भी बदलाव को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह अधिसूचना के जरिए लागू हो गया। हर नए नियम के साथ तीन सवाल अनिवार्य होने चाहिए। क्यों बदला, किस पर असर पड़ेगा और जनता को इससे क्या मिलेगा? यदि किसी बदलाव से व्यवस्था बेहतर होती है, उपभोक्ता को सुविधा मिलती है, धोखाधड़ी कम होती है या सेवाएं अधिक पारदर्शी बनती हैं, तो उसका औचित्य स्पष्ट है। लेकिन यदि नागरिक को सिर्फ नई फीस, नई शर्त और नई प्रक्रिया मिलती है, तो उससे सवाल पूछना भी उतना ही जायज है। खासकर मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह सवाल और गंभीर है। उनकी आमदनी में अचानक बड़ी छलांग नहीं लगती, लेकिन खर्चों में छोटे-छोटे इजाफे लगातार जुड़ते रहते हैं। एक ओर उनसे डिजिटल और वित्तीय रूप से जागरूक होने की अपेक्षा की जाती है, दूसरी ओर नियमों का जाल लगातार जटिल होता जाता है। नागरिक को जागरूक बनाना और नागरिक को नियमों के बोझ तले दबाना दोनों एक बात नहीं हैं। इसलिए अब जरूरत केवल हर महीने बदलाव घोषित करने की नहीं, बल्कि बदलाव की। जनता-केंद्रित व्याख्या करने की है। पहली तारीख से पहले स्पष्ट रूप से बताया जाए कि क्या बदलेगा, किस तारीख से बदलेगा, किस वर्ग पर कितना असर पड़ेगा और नागरिक अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। यही वास्तविक पारदर्शिता होगी। आखिर लोकतंत्र में नागरिक केवल नियम मानने वाला व्यक्ति नहीं है। वह व्यवस्था का केंद्र है। उसकी जेब, उसका समय और उसकी सुविधा भी नीतियों की सफलता की कसौटी होनी चाहिए। पहली तारीख को नियम बदलना आसान है। मुश्किल काम यह सुनिश्चित करना है कि हर बदलाव के बाद आम आदमी खुद को थोड़ा और असुरक्षित, थोड़ा और असहाय और थोड़ा और महंगा जीवन जीने को मजबूर न जाए। कैलेंडर की पहली तारीख हर महीने लौटती है। अब सवाल यह है कि उसके साथ लौटने वाला संदेश क्या होगा कि व्यवस्था नागरिक के लिए आसान हुई, या नागरिक की जेब पर एक और नया बोझ डाल दिया गया? जनता को बदलाव से समस्या नहीं है। समस्या तब है, जब हर बदलाव का बिल भी जनता के नाम ही लिखा जाए।

यूपीआई में टैक्स लगाये जाने के विरोध में दिशा ने भेजा वित्त मंत्री को ज्ञापन

संवाददाता
देहरादून। यूपीआई में टैक्स लगाये जाने के विरोध में दिशा सामाजिक संस्था ने जिला प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।

आज यहां दिशा सामाजिक संस्था के पदाधिकारी अध्यक्ष सुशील विरमानी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए जहां से उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा यूपीआई में टैक्स लगाया गया है वह उचित नहीं है इससे आम नागरिक एवं व्यापारियों को असुविधा होगी, साथ ही व्यापार प्रभावित होगा। आमजन पर पहले ही इतने टैक्स लगा दिये गये हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। यदि टैक्स अनिवार्य है तो इसकी सीमा बढ़ायी जाये जिससे जन हित में सरकार व आमजन को लाभ मिले। ज्ञापन देने वालों में पंकज नेगी, प्रभात डंडरियाल, बृज मोहन, विजन, अनुप गुप्ता, विनित बडथवाल, शिव कुमार, रंजीत सिंह शामिल रहे।



संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। भाजपा ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास का माहौल बनाने और नकारात्मक नैरेटिव को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े करना राजनीतिक असहमति से आगे की बात है और इससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस को चुनावी मुद्दों पर जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पार्टी के मुताबिक, संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है, लेकिन आरोपों के साथ ठोस तथ्य और प्रमाण भी सामने रखे जाने चाहिए।

भाजपा का यह हमला ऐसे समय में आया है, जब मतदाता सूची, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कांग्रेस



◆ भाजपा बोली नकारात्मक नैरेटिव से कांग्रेस की हताशा उजागर
◆ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा मजबूत करने की आज जरूरत
◆ कांग्रेस के आरोपों को बताया है राजनीतिक रणनीति का हिस्सा

लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावी पारदर्शिता और मताधिकार से जोड़ रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बता रही है। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की है। ऐसे में बिना ठोस आधार के लगातार अविश्वास का वातावरण बनाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे पर असर पड़ सकता है। पार्टी ने कांग्रेस से आरोपों के बजाय तथ्य सामने रखने को कहा है।

विद्यालय परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर कैबिनेट मंत्री ने दिया स्वच्छता का संदेश

संवाददाता
देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विद्यालय परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया।

आज यहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कालीदास रोड स्थित एसजीआरआर पब्लिक स्कूल में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित स्वच्छ भारत अभियान एवं 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विद्यालय परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और विद्यार्थियों को स्वच्छता के



प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, विचारों और व्यवहार का अभिन्न हिस्सा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता को विशेष महत्व दिया था। जिसको आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान की

युवाओं में राष्ट्रवादी विचारों की मजबूती का संकेत

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में युवाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसी बीच युवाओं के बीच राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े विचारों की स्वीकार्यता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा इसे युवाओं में राष्ट्रवादी विचारों की मजबूती का संकेत मान रही है और इसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देख रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आज का युवा केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की वैश्विक भूमिका, सेना, सीमांत क्षेत्रों और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर भी अपनी राय रखता है। पार्टी के मुताबिक युवाओं में इन विषयों को लेकर बढ़ती रुचि उसके लिए सकारात्मक संकेत है।

उत्तराखंड के संदर्भ में यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की बड़ी आबादी का सामाजिक और आर्थिक संबंध सेना तथा पूर्व सैनिक परिवारों से जुड़ा रहा है। सीमांत जिलों की भौगोलिक परिस्थितियां

और सैन्य परंपरा भी राष्ट्र और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को यहां विशेष महत्व देती हैं। भाजपा इसी सामाजिक पृष्ठभूमि को अपनी राजनीतिक संवाद रणनीति से जोड़ रही है। हालांकि, युवाओं की राजनीतिक प्राथमिकताएं केवल राष्ट्रवाद तक सीमित

◆ भाजपा ने युवाओं के रुझान को बताया बदलती राजनीतिक सोच का संकेत
◆ प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती
◆ चुनावी समर्थन का सीधा संकेत मानना राजनीतिक दलों के लिए जल्दबाजी

नहीं हैं। रोजगार, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, शिक्षा, पलायन, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर अवसर जैसे मुद्दे भी उत्तराखंड के युवा मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए युवाओं के बीच राष्ट्रवादी विचारों की मौजूदगी को चुनावी समर्थन का सीधा संकेत मानना राजनीतिक दलों के लिए जल्दबाजी होगी।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल युवाओं के सवाल को रोजगार और आर्थिक अवसरों से जोड़कर सरकार को घेरते रहे हैं। उनका

हालांकि, कांग्रेस का पक्ष इससे अलग है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाना लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है। पार्टी का तर्क है कि यदि किसी प्रक्रिया में उसे कोई आपत्ति दिखाई देती है तो उसे सार्वजनिक करना संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस इसे संस्थाओं के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा सवाल बताती रही है। यही विरोधाभास अब उत्तराखंड की राजनीति में बढ़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा इसे कांग्रेस की हताशा और नकारात्मक राजनीति के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक निगरानी और चुनावी पारदर्शिता का प्रश्न बता रही है।

विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने के साथ आने वाले दिनों में यह टकराव और बढ़ सकता है। खासतौर पर मतदाता सूची और एसआईआर जैसे मुद्दे यदि चुनावी बहस के केंद्र में आते हैं तो दोनों दलों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। ऐसे में असली कसौटी यही होगी कि आरोपों और राजनीतिक दावों के बीच तथ्य कितने स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखे जाते हैं।

शुरुआत की गई, जिसने स्वच्छता को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमें अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, उसी प्रकार मन और विचारों की स्वच्छता भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि मन में गंदगी और नकारात्मकता है तो उसे भी दूर कर अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए और इसे केवल अभियान तक सीमित न रखते हुए अपने दैनिक जीवन और विचारों में शामिल करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का विशेष महत्व है।

जोर इस बात पर है कि राष्ट्र निर्माण की चर्चा के साथ युवाओं को रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर भी चाहिए। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के बीच राजनीतिक विमर्श का स्वरूप महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रवाद बनाम रोजगार जैसी सरल राजनीतिक तस्वीर से आगे युवाओं के सामने कई मुद्दे एक साथ मौजूद हैं। भाजपा राष्ट्रवादी विमर्श को मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष रोजगार, शिक्षा और सरकार के प्रदर्शन से जुड़े सवालों को प्रमुखता देने की रणनीति अपना सकता है।

उत्तराखंड में युवा मतदाता किस मुद्दे को कितना महत्व देता है, इसका आकलन केवल राजनीतिक दलों के दावों से नहीं, बल्कि चुनावी आंकड़ों और जमीनी रुझानों से ही संभव होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि युवाओं को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति तेज हो गई है और राष्ट्रवाद भी इस राजनीतिक संवाद का एक प्रमुख हिस्सा बनता जा रहा है।

उत्तराखंड में 826 स्कूलों पर ताले

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे होने के बाद विकास की उपलब्धियों के बीच सरकारी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ पहाड़ के गांवों से लगातार घटती छात्र संख्या के कारण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ जिन विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। पिछले पांच वर्षों में शून्य छात्र नामांकन के कारण 826 सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद अथवा दूसरे विद्यालयों में विलय किए जा चुके हैं। वहीं नवीनतम यूडीआईएसई 2025-26 के अनुसार राज्य में 2,655 विद्यालय ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक तैनात है। माध्यमिक शिक्षा का संकट इससे अलग और अधिक गंभीर है। राज्य में 4,745 प्रवक्ता पद रिक्त हैं। इनमें से 808 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, जबकि 3,937 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं और न्यायिक रोक के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित है। इसका असर विषयवार पढ़ाई से लेकर विद्यालयों के प्रशासन तक दिखाई दे रहा है।

सरकार की ओर से विधानसभा में रखे गए आंकड़े बताते हैं कि विद्यालय बंद होने की समस्या मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्रित है। पांच वर्षों में सबसे अधिक 262 प्राथमिक विद्यालय टिहरी गढ़वाल में बंद हुए। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल में 120, पिथौरागढ़ में 104 और अल्मोड़ा में 83 विद्यालय बंद हुए। नैनीताल में 49, चमोली में 43, देहरादून में 38, चंपावत में 34, बागेश्वर में 30, उत्तरकाशी में 25, ऊधमसिंह नगर में 21, रुद्रप्रयाग में 15 और हरिद्वार में दो विद्यालय बंद हुए। इन आंकड़ों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सरकारी स्कूलों के बंद होने की कहानी केवल शिक्षा विभाग की प्रशासनिक कवायद नहीं है। इसके पीछे पहाड़ के गांवों में बदलती जनसंख्या का संकट भी जुड़ा हुआ है। जिस गांव में बच्चों की संख्या लगातार घटती जाती है, वहां विद्यालय चलाना विभाग के लिए कठिन होता जाता है। लेकिन दूसरी तरफ विद्यालय का बंद होना उस गांव के सामाजिक जीवन को और कमजोर कर सकता है। यानी सवाल केवल यह नहीं है कि विद्यालय में बच्चे कितने हैं। सवाल यह भी है कि बच्चे गांव में क्यों नहीं हैं और गांव में बच्चों को रोकने के लिए शिक्षा व्यवस्था कितनी सक्षम है।

जिलेवार आंकड़ों में पर्वतीय और मैदानी उत्तराखंड के बीच का अंतर भी साफ दिखाई देता है। टिहरी में 262 विद्यालय बंद हुए, जबकि हरिद्वार में केवल दो। पौड़ी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जैसे पर्वतीय जिलों में भी बंद विद्यालयों की संख्या काफी अधिक रही। यह अंतर उत्तराखंड के उस पुराने सवाल को सामने लाता है, जिस पर राज्य बनने के बाद से लगातार चर्चा होती रही है कि क्या पहाड़ में शिक्षा की व्यवस्था केवल विद्यालय खोलकर मजबूत की जा सकती है, या इसके लिए गांवों में आबादी और रोजगार का टिकना भी जरूरी है? यदि गांवों से परिवार बाहर जा रहे हैं, खेती और स्थानीय रोजगार के अवसर घट रहे हैं

और नई पीढ़ी शिक्षा व रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर जा रही है, तो विद्यालयों में नामांकन स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा। लेकिन विद्यालय बंद होने के बाद बचे हुए परिवारों के बच्चों को दूर स्थित विद्यालय तक पहुंचाने की समस्या भी बढ़ती है।

उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की दूसरी बड़ी चुनौती शिक्षक उपलब्धता है। नवीनतम यूडीआईएसई 2025-26 में राज्य के 2,655 एकल-शिक्षक विद्यालय दर्ज हैं। संसद में प्रस्तुत केंद्र सरकार के आंकड़ों में भी उत्तराखंड के लिए यही संख्या दर्ज है। इससे पहले राज्य में 2,959 एकल-शिक्षक विद्यालय होने की रिपोर्ट सामने आई थी। इस आंकड़े को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में भी चिंता जताई गई। बाद के यूडीआईएसई आंकड़े में संख्या 2,655 दर्ज है। इसलिए अलग-अलग रिपोर्टों में संख्या का अंतर रिपोर्टिंग वर्ष और आंकड़ों के स्रोत के कारण हो सकता है। एकल-शिक्षक विद्यालय की वास्तविक चुनौती पहाड़ी क्षेत्रों में और अधिक जटिल हो जाती है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को एक साथ अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को संभालना पड़ता है। पढ़ाई के अलावा प्रशासनिक कार्य, अभिलेख, विभागीय सूचनाएं और अन्य जिम्मेदारियां भी उसी शिक्षक के हिस्से में आती हैं।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक शिक्षक से एक साथ शिक्षण, मूल्यांकन, प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन की सभी जिम्मेदारियां निभाने की अपेक्षा किस हद तक व्यावहारिक है। प्राथमिक विद्यालयों में जहां छात्र संख्या और एकल शिक्षक बड़ी समस्या है, वहीं माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक पदों की रिक्तियां चिंता बढ़ा रही हैं। राज्य में 4,745 प्रवक्ता पद खाली बताए गए हैं। सरकार के अनुसार 808 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन 3,937 पद पदोन्नति से भरे जाने की प्रक्रिया न्यायिक रोक के कारण प्रभावित हुई। इसका सीधा असर उन विद्यालयों पर पड़ता है जहां किसी विषय का स्थायी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। विज्ञान, गणित, भाषा और अन्य विषयों में शिक्षक की कमी का प्रभाव विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर पड़ सकता है। यहां शिक्षा व्यवस्था का एक विरोधाभास भी सामने आता है कि एक ओर कई विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी कम है कि विद्यालय बंद करने की नौबत



◆ 2655 विद्यालय है मात्र एक शिक्षक के भरोसे
◆ खाली गांवों से सिकुड़ रहा शिक्षा का आधार
◆ माध्यमिक स्तर पर 4745 प्रवक्ता पद खाली
◆ 3937 पदों की पदोन्नति न्यायिक अड़चन में

आ रही है, दूसरी ओर मौजूद विद्यालयों में हजारों शिक्षक पद खाली हैं।

शिक्षा व्यवस्था में केवल शिक्षकों की कमी ही नहीं है। विद्यालयों के प्रशासनिक नेतृत्व का संकट भी सामने है। सल्ट विधानसभा क्षेत्र में 59 माध्यमिक विद्यालयों में से 37 में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं हैं। इन विद्यालयों में कार्यवाहक व्यवस्था के सहारे काम चलाया जा रहा है। प्रधानाचार्य किसी विद्यालय में केवल प्रशासनिक पद नहीं होता। विद्यालय की शैक्षणिक योजना, शिक्षकों के बीच समन्वय, अनुशासन, अभिभावकों से संवाद और विभागीय कार्यों में प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लंबे समय तक स्थायी प्रधानाचार्य नहीं होने से विद्यालय संचालन पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। शिक्षक और छात्र संकट के साथ सरकारी विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार 2,210 सरकारी विद्यालयों की इमारतों की स्थिति खराब बताई गई है। 2024-25 के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट में पौड़ी गढ़वाल में ऐसे विद्यालयों की संख्या 330 बताई गई थी। उसी रिपोर्ट में 361 विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय और 130 विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं होने की जानकारी दी गई थी।

जर्जर विद्यालय भवनों का संकट नया नहीं है। शिक्षा विभाग ने पहले भी वर्षाकाल में ऐसे भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। 2023 की विभागीय रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में 2,785 सरकारी स्कूल भवनों को जर्जर बताया गया था, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि अलग-अलग

वर्षों और मानकों के कारण जर्जर भवनों के आंकड़ों में अंतर मिलता है। विद्यालय में शिक्षक और भवन होने के बाद भी यदि बिजली, पानी, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल बना रहता है। पुराने सरकारी आंकड़ों में उत्तराखंड के बड़ी संख्या में विद्यालयों में बिजली, पुस्तकालय, खेल मैदान, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं की कमी दर्ज की गई थी। समय के साथ कई सुविधाओं में सुधार हुआ है, इसलिए पुराने आंकड़ों को वर्तमान स्थिति का सीधा प्रतिनिधि मानना उचित नहीं होगा। फिर भी पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयां, मौसम, सड़क संपर्क और निर्माण की लागत जैसी समस्याएं शिक्षा के बुनियादी ढांचे को लगातार चुनौती देती हैं।

उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों की मौजूदा तस्वीर को केवल शिक्षा विभाग की विफलता या उपलब्धि के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके पीछे पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क संपर्क और गांवों की जनसांख्यिकी भी जुड़ी है। यदि किसी गांव में परिवार ही नहीं बचेंगे तो विद्यालय में विद्यार्थी कहां से आएंगे? और यदि विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो गांव में बचे परिवार अपने बच्चों को लेकर वहां कितने समय तक टिके रहेंगे? यही वह बिंदु है जहां शिक्षा और पलायन का रिश्ता एक-दूसरे को प्रभावित करता दिखाई देता है। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई पहल कर रही है। मार्च 2026 में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की ओर से विद्यालयी शिक्षा

में आधारभूत ढांचे, आधुनिक संसाधनों, नई शिक्षण पद्धतियों और शिक्षक कौशल पर जोर दिए जाने की बात कही थी। समग्र शिक्षा उत्तराखंड के स्तर पर भी शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय सुधार से जुड़ी गतिविधियां जारी हैं। 2026 में 50 सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण माडल लागू करने की पहल भी सामने आई है।

सरकार शिक्षा में फिनलैंड जैसी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से सीख लेने की दिशा में भी विचार कर रही है। लेकिन फिनलैंड की किसी पद्धति को अपनाने से पहले उत्तराखंड की अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों, शैक्षणिक स्वायत्तता, सीखने में समान अवसर और विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार सहायता पर जोर दिया जाता है। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के सामने अब केवल यह चुनौती नहीं है कि कितने विद्यालय बनाए जाएं। चुनौती यह भी है कि कितने विद्यालय बचाए जाएं, कितने बच्चों को गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और कितने परिवारों को गांव छोड़ने से रोका जा सके। 826 विद्यालयों का बंद होना महज 826 भवनों का खाली होना नहीं है। प्रत्येक विद्यालय किसी गांव के सामाजिक और सामुदायिक जीवन का केंद्र भी रहा है। विद्यालय बंद होने का अर्थ कई जगहों पर बच्चों को दूसरे गांव तक भेजना, अभिभावकों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी और गांव के सार्वजनिक जीवन में एक और कमी होना है। दूसरी ओर हजारों विद्यालयों का एक शिक्षक के भरोसे चलना बताता है कि जहां विद्यार्थी मौजूद हैं, वहां पर्याप्त मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। माध्यमिक स्तर पर 4,745 प्रवक्ता पदों की रिक्ति और 3,937 पदोन्नतियों का न्यायिक अड़चन में फंसना इस संकट को और बड़ा करता है। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि सरकार बंद हो चुके विद्यालयों की संख्या गिनने से आगे बढ़कर उन कारणों को कैसे संबोधित करेगी, जिनकी वजह से विद्यालय खाली हुए और जो विद्यालय चल रहे हैं, वहां बच्चों को पर्याप्त शिक्षक, सुरक्षित भवन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब तक मिलेगी। क्योंकि पहाड़ में स्कूल का बचना केवल शिक्षा विभाग की उपलब्धि नहीं होगा कि यह उस गांव में जीवन के बचे रहने का भी संकेत होगा।

टिहरी जिले में सड़क हादसे 41 फीसदी बढ़े

नई टिहरी (आरएनएस)। टिहरी जिले में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी से अगस्त 2025 तक जिले में 43 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी जबकि इसी अवधि में 2026 में हादसों की संख्या बढ़कर 61 पहुंच गई। एक साल में दुर्घटनाओं में करीब 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हादसों के कारणों और रोकथाम के उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में एसएसपी श्वेता

चौबे समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनवरी से अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में जून और अप्रैल में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं। हादसों के मुख्य कारण अंधे मोड़, वाहन चलाने में लापरवाही और चालक का ध्यान भटकना सामने आया। डीएम ने लोनिवि, राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलिस अधिकारियों को जिले के सभी अंधे मोड़ों को चिह्नित कर उनका सर्वे करने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। देवप्रयाग क्षेत्र में अधिक सड़क

दुर्घटनाओं को देखते हुए डीएम ने वहां एएनपीआर कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। ढलान वाले मार्गों पर तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करने को भी कहा। कार्यदायी संस्था को सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई का काम अगले 15 दिनों के अंतर्गत पूरा करने को कहा। बैठक में एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी, लोनिवि अधीक्षण अभियंता केएस नेगी, ईई आरके टम्टा, बीआरओ के.सी. नौटियाल, एआरटीओ राजेंद्र विराटिया आदि मौजूद रहे।

हरिद्वार जिले में गन्ना मंत्री के विरोध की चेतावनी

रुड़की (आरएनएस)। उत्तराखंड किसान मोर्चा का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 42वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता चौधरी राजेंद्र सिंह ने की, जबकि संचालन मोहम्मद रफी ने किया।

इस दौरान किसानों ने गन्ना मूल्य और बकाया भुगतान समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने गन्ना मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके हरिद्वार जिले में आने पर विरोध करने की चेतावनी दी।

शब्द सामर्थ्य - 59

(भागवत साहू)

अच्छी शिक्षा, नेक सलाह 5. आवागमन, गमनागमन 7. पुरुष 8. घोड़े की तेज चाल, तेज गति की दौड़ 10. लूटपाट, डकैती 12. बबादी, तबाही 14. नासिका, श्वसनइंद्रिय 17. आखेटक, अरेही 19. योग्य, काबिल 20. कामदेव की पत्नी, प्रेम, आनंद 21. रात्रि, निशा।

बाएं से दाएं

1. तकलीफ, कष्ट, कठिनाई, परेशानी 3. सरल, सहज 6. ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा लेना 7. विवश, लाचार 8. अत्यधिक ठंडा, सुस्त 9. अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत 11. सूर्य, सूरज 13. वस्त्र आदि धारण करना 15. अप्रसन्न,

ऊपर से नीचे

1. हृदय, उर 2. शिष्टता, भद्रता, विवेक (उ.) 3. अंततः, अंततोगत्वा

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 58 का हल

चु	स्त		मु		सं	स्था	न	
ग		म	र्दा	न	गी		त	म
ली	प	ना			त	न		
	ना	ना					ज	
मा	ह		रा		सा	ज	न	
न		स	ह	दे	व		म	द
व		म		व	न	ज		ल
ता	क	त	व	र		मी		द
	ल	ल	क		क	र	त	ल

1		2		3		4		5
						6		
	7							
8						9	10	
				11	12			
13			14		15			
			16	17			18	19
	20					21		
22						23		

क्या काम से आपका भी भटक जाता है ध्यान...!

इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित होता है। 9 टू 6 ऑफिस, खराब खानपान, खराब दिनचर्या के चलते हमारा फोकस डांवाडोल होता जा रहा है। इसके अलावा और भी कई कारण जिम्मेदार हैं। काम कुछ और होता है और हमारा ध्यान कहीं और रहता है। पढ़ाई करने वालों से लेकर कामकाजी लोग तक सब डिस्ट्रैक्शन के शिकार होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। आप भी काम करते वक्त डिस्ट्रेक्ट हो जाते हैं। तो आप इन टिप्स की मदद से इससे डील कर सकते हैं।

डिस्ट्रैक्शन से डील करने के टिप्स

1- डिस्ट्रैक्शन से डील करने के लिए किसी भी काम को करने से पहले 1 दिन पहले ही सारी योजनाएं तैयार कर लें, ताकि आप को ये सोचते हुए पूरा दिन ना चला जाए कि काम को कैसे करना है।

2- मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाना भी जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया स्कॉल करने से आपका ध्यान भटक जाता और आपका फोकस काम पे नहीं रह पाता। ईमेल चेक करने, फोन कॉल करने या सोशल मीडिया फीड पढ़ने से पहले अपने कामों का खत्म करने का लक्ष्य बनाएं ऐसा करने से आप बिना डिस्ट्रैक्शन किसी भी काम को समय पर पूरा कर पाएंगे।

3- आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांति देता है। दिमाग में आने वाले ख्यालों को छोड़ आपको एक चीज पर फोकस करने की अनुमति देता है। ये चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी किसी भी मानसिक गड़बड़ी को दूर करता है।

4- 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लेना शुरू कर दें। अगर आप कम नींद लेते हैं तो इससे भी आपको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। नींद से शरीर को एनर्जी मिलती है। यह एक तरह की हीलिंग प्रोसेस है। इससे मेमोरी बूस्ट होता है। इसकी कमी के कारण काम की स्पीड कम होती है। काम में मन कम लगता है। हर वक्त आपको आलस महसूस होता है।

5- मल्टी टास्किंग होने से बचें। एक बार में एक काम करने से आपको जरूरी काम पर फोकस करने में मदद मिलती है और आपके काम की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो इससे आप कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे।

6- काम के बीच में ब्रेक लेने से भी आप डिस्ट्रैक्शन से डील कर सकते हैं। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो ऐसे आपको अधिक थकान महसूस होगी, जिस वजह से आप लंबे वक्त तक अपने काम पर फोकस नहीं रख पाएंगे। बिना ब्रेक लिए काम करने से फोकस कम हो जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि नियमित रूप से ब्रेक लेते रहें।

प्रेग्नेंट महिलाओं को प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं चाहिये

यह एक जाना माना तथ्य है कि प्लास्टिक के डिब्बे में खाना गरम करने या प्लास्टिक की बोतल में रखा पानी पीने से कैंसर हो सकता है क्योंकि प्लास्टिक में उपस्थित रसायन खाद्य पदार्थों में पहुँच जाते हैं तथा फिर इन खाद्य पदार्थों के द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गरम न करने की सलाह दी जाती है।

गर्मी के कारण प्लास्टिक के बर्तनों से कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन उत्सर्जित होते हैं जो खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और प्लास्टिक में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं को डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इन डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायन होते हैं तथा प्लास्टिक के बर्तनों में खाद्य पदार्थों को गर्म करने से खाद्य पदार्थ भी इन हानिकारक रसायनों से दूषित हो जाते हैं।

प्लास्टिक के बर्तनों या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में केवल हानिकारक रसायन ही नहीं होते बल्कि इसमें डब्ल्यू बिस्फेनोल ए भी होता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में समस्या उत्पन्न कर सकता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और प्लास्टिक में रखे खाद्य पदार्थों का गर्भवती महिलाओं पर क्या दुष्परिणाम होता है यह जानने के लिए लेख पढ़ें।

हार्मोन्स में गड़बड़ी उत्पन्न करना यदि कोई गर्भवती महिला प्लास्टिक के बर्तन में गर्म किया हुआ खाना खाती है, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीती है या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खाती है तो यह उसके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसके कारण बच्चे में मानसिक और शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं जिसमें मस्तिष्क से संबंधित बीमारियाँ भी शामिल हैं। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं होता प्लास्टिक के बर्तनों में पाए जाने वाले इस रसायन के कारण माताओं में एस्ट्रोजन बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है। यह बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है तथा महिलाओं (तथा पुरुषों में भी) प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः सभी गर्भवती महिलाओं को प्लास्टिक के बर्तनों में खाना न खाने, खाना गर्म न करने तथा प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ न खाने की सलाह भी जाती है।

बिस्फेनोल ए कई देशों में प्रतिबंधित है कुछ देशों जैसे चीन, फ्रांस और कनाडा ने उन सभी उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिनमें यह रसायन होता है। यदि किसी उत्पाद में पाया जाता है तो तुरंत उसका उत्पादन रोक दिया जाता है। यही कारण है कि आजकल प्लास्टिक के बर्तनों पर हम एक लेबल लगा हुआ देखते हैं जिस पर बिस्फेनोल ए फ्री लिखा होता है।

सुबह बिना ब्रश किए पानी पीना सही है ?

शरीर के लिए पानी कितना ज्यादा जरूरी है यह बात किसी से छिपी नहीं है। बहुत सारी पेट की बीमारी और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी बहुत 'यादा जरूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन कई लोग सुबह ब्रश करने से पहले बासी मुंह पानी पीते हैं। आज हम जानेंगे क्या ऐसा करना सच में सेहत के लिए फायदेमंद है।

ब्रश करने से पहले पानी पीने के फायदे डाइजेशन होता है बेहतर: अगर आप ब्रश करने से पहले बासी मुंह पानी पीते हैं तो ऐसा करने से आपकी पाचन शक्ति अ'छी होती है। साथ ही आपका खाना आसानी से पच जाता है। शरीर में जमी कई बीमारियां जैसे- आलस आना, पित्तस होना, पेट की बीमारी, अनपच की दिक्कत, अगर आप बासी मुंह बिना ब्रश किए पानी पीते हैं तो आपके शरीर की गंदगी निकल जाती है।

सुबह के वक्त शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है: सोने के दौरान यानि 7-8 घंटे के बीच तो हम पानी पीते नहीं हैं। ऐसे में आपको सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए। ताकि आपका शरीर सबसे पहले हाइड्रेट रहे।

मुंह में बैक्टीरिया नहीं होता है जमा:

चुटकी में थकान को दूर भगाएं

इस भागदौड़ भरी जिन्दगी से कुछ आराम के लम्हे निकाल कर तो देखिए, तन हमेशा स्वस्थ और मन सदा प्रसन्न रहेगा किसी को बैठकर काम करना होता है तो किसी को खड़े रह कर तो किसी को चलफिर कर। किसी को शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो किसी को मानसिक। पर एक बात तय है, थकान सभी को होती है। थकान दूर करने में पानी की भूमिका महत्वपूर्ण है। गरम पानी की बोतल से सिंकाई करने से प्रभावित अंग के दर्द में आराम मिलेगा और थकान भी दूर होती है। काम के बीच ठंडे पानी से हाथमुंह धोएं व आंखों में पानी के छींटे मारें। काम करने की अवधि में आराम का अवसर ना मिले तो आंखो बंद कर के उन पर अपनी हथेलियां रख कर ढक लें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और थकान भी कम होगी। अपने विचारों को सकारात्मक रूप देना, अच्छे पलों को याद रखना, सदा प्रसन्न रहना, हंसेने- हंसाने का गुण अपनाना आदि थकान से बचने के सही उपाय हैं।

बालों में तेल से ज्यादा सिर की मालिश जरूरी



बालों में ढेर सारा तेल लगाने के बाद भी अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं या फिर असमय ही सफेद होते चले आ रहे हैं, तो इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है कि क्या तेल लगाने से तो ऐसा नहीं हो रहा है। बालों में जो तेल आप लगा रहे हैं, क्या वह आपको सूट भी कर रहा है? क्या अपने बाल लंबे और घने करने के चक्कर में आप जरूरत से ज्यादा ऑयलिंग तो नहीं कर रहे हैं?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेल की आवश्यकता आपके बालों को नहीं बल्कि आपकी स्कैल्प को होती है। इसलिए यह धारणा जितनी जल्दी हो सके बदल लें। आइए जानते हैं कि बालों में हद



मुंह में जमे जितने भी जर्म्स होते हैं। बासी मुंह पानी पीने से मुंह जर्म फ्री हो जाते हैं। इम्युनिटी बढ़ती है: अगर आप बासी में पानी पिएंगे तो आपकी इम्युनिटी बढ़ेगी। आपको जल्दी-जल्दी कोल्ड या कफ नहीं होगा। इससे बाल भी हेल्दी होते हैं।

सुबह बासी मुंह पानी पीने से आप हाई बीपी और शुगर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही सुबह अगर आप पानी पीते हैं तो आप मोटापे जैसी समस्या से बच सकते हैं। अगर आपको वजन कम

करना है तो बासी मुंह जरूर पानी पिएं। सुबह बासी मुंह पानी पीना अ'छा माना जाता है। मुंह से बदबू नहीं आती है : ड्राई माउथ के कारण मुंह से बदबू आती है। ऐसे में अगर आप सुबह उठकर बासी मुंह से पानी पिएंगे तो आप कई तरह के समस्या से बच सकते हैं। ड्राई माउथ की समस्या तब होती है जब आप जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पीते हैं, इसलिए सुबह उठकर पानी जरूर पानी पीना चाहिए।



इस भागदौड़ भरी जिन्दगी से कुछ आराम के लम्हे निकाल कर तो देखिए, तन हमेशा स्वस्थ और मन सदा प्रसन्न रहेगा किसी को बैठकर काम करना होता है तो किसी को खड़े रह कर तो किसी को चलफिर कर। किसी को शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो किसी को मानसिक। पर एक बात तय है, थकान सभी को होती है। थकान दूर करने में पानी की भूमिका महत्वपूर्ण है। गरम पानी की बोतल से सिंकाई करने से प्रभावित अंग के दर्द में आराम मिलेगा और थकान भी दूर होती है। काम के बीच ठंडे पानी से हाथमुंह धोएं व आंखों में पानी के छींटे मारें। काम करने की अवधि में आराम का अवसर ना मिले तो आंखो बंद कर के उन पर अपनी हथेलियां रख कर ढक लें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और थकान भी कम होगी। अपने विचारों को सकारात्मक रूप देना, अच्छे पलों को याद रखना, सदा प्रसन्न रहना, हंसेने- हंसाने का गुण अपनाना आदि थकान से बचने के सही उपाय हैं।

बालों में तेल से ज्यादा सिर की मालिश जरूरी

है, जिससे बाल लंबे-घने और काले होते हैं।

इन दिनों बालों के लिए तरह-तरह के तेलों के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन आपको सिर्फ प्राकृतिक तेलों को ही तवज्जो देनी चाहिए, जैसे- ऑलिव ऑयल, नारियल तेल, नीम का तेल, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल, चमेली का तेल, पेपरमिंट ऑयल, तिल का तेल, बादाम का तेल, भृंगराज तेल, लैवेंडर ऑयल आदि।

फिजी बालों के लिए नहीं चलेगा सिर्फ तेल से काम

यदि आपका सिर रूखा है और यह सोच कर ढेर सारा तेल लगा लेते हैं कि उससे बाल नरम हो जाएंगे तो ऐसा न करें। ढेर सारा तेल लगाने से स्कैल्प के पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं और उनमें गंदगी भरने लगती है। ऐसा लगातार करने से सिर में फंगल इंफेक्शन भी सकता है।

क्या करें जब तेल से हो एलर्जी अगर आपके स्कैल्प को तेल से एलर्जी है, तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे आपके बालों को भरपूर्ण पोषण मिल सकता है। आप चाहें तो बालों में हर सप्ताह अंडे का हेयर पैक बना कर लगा सकती हैं। इसके अलावा हिना पाउडर का पेस्ट, आंवला और अश्वगंधा भी बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

यूकेडी में पूर्व कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष समेत दर्जनों लोग शामिल

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तराखंड क्रांति दल की अल्मोड़ा इकाई के जिला कार्यालय में महानगर अध्यक्ष मोहित साह की अध्यक्षता में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अल्मोड़ा और जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के पूर्व नगर उपाध्यक्ष अमरेश पवार ने अपने साथियों के साथ यूकेडी की सदस्यता ली। पवार ने कहा कि उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय दलों का रुख उदासीन रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय पार्टी के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा कि पहाड़ के लोगों के स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकारों के लिए उन्होंने यूकेडी की सदस्यता ली है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में यूकेडी प्रत्याशी के समर्थन में अपने साथियों के साथ खड़े रहने की बात कही। सदस्यता लेने वालों में विनोद कुमार टम्टा, हरीश कुमार, बाला देवी, कमला देवी, पंकज कुमार टम्टा, मोनू कुमार, रघुवर सिंह बिष्ट, गोपाल राम, विक्रम वाल्मीकि, सूरज टम्टा, कैलाश चंद्र, पारस बजाज, अर्जुन वाल्मीकि, रोबिन वाल्मीकि, विकी कुमार और विजय कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में यूकेडी जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी, विनय किरौला, केंद्रीय मंत्री गिरीश नाथ गोस्वामी, महानगर अध्यक्ष मोहित साह, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष वंश कनवाल, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रवि नेगी, महामंत्री प्रताप सिंह बिष्ट, सुजीत टम्टा और प्रकाश बिष्ट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

संसद की अनुमान समिति सदस्यों ने ऋषिकेश में गंगा आरती की

ऋषिकेश(आरएनएस)। संसद की अनुमान समिति के सदस्य सांसद एमके राघवन सहित कई अधिकारियों का दल परमार्थ निकेतन पहुंचा। उन्होंने परमार्थ निकेतन में गंगा आरती की और भारतीय संस्कृति, सनातन परम्परा और आध्यात्मिक चेतना का अनुभव किया। परमार्थ निकेतन में भारत की संसद की अनुमान समिति के सदस्य सांसद एमके राघवन पहुंचे। सांसद ने परमार्थ पीठाधीश्वर स्वामी चिदानन्द सरस्वती एवं डॉ. साध्वी भगवती सरस्वती के सान्निध्य में गंगा आरती एवं यज्ञ में सहभाग किया। सांसद एमके राघवन ने कहा कि परमार्थ निकेतन की गंगा आरती एक दिव्य धार्मिक अनुष्ठान है जो प्रकृति, संस्कृति और मानवता के बीच सामंजस्य का संदेश देने वाली एक जीवंत परम्परा है। उन्होंने कहा कि अनुमान समिति का यह अध्ययन दौरा विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणाली, व्यवस्थाओं, गतिविधियों एवं विकास से जुड़े पहलुओं के प्रत्यक्ष अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की यात्रा के दौरान परमार्थ निकेतन का यह प्रवास भारतीय संस्कृति और आधुनिक विकास के बीच संवाद का भी एक सुंदर अवसर बना।

सू- दोकू क्र. 59

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

- कुल 81 वर्ग है, जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
- हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
- बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र. 58 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

सीएचसी धौलादेवी में अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे मशीन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू

अल्मोड़ा(आरएनएस)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी में अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित करने की मांग को लेकर डॉ. नीरज पंत के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। पहले दिन क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने धरने को समर्थन दिया।

सुबह करीब 11 बजे क्षेत्र के ग्राम प्रधान धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन के समर्थन में एकजुटता जताई। प्रधान संगठन ने आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान शुरू करने की बात कही। आंदोलनकारियों ने कहा कि अस्पताल में जरूरी जांच सुविधाएं नहीं होने के कारण

कालाढूंगी में निहाल नदी पर बनेगा आरसीसी पुल

हल्द्वानी(आरएनएस)। कालाढूंगी क्षेत्र के चकलुवा में निहाल नदी पर बने वेली ब्रिज की जगह अब जल्द नया आरसीसी पुल बनेगा। यह जानकारी विधायक बंशीधर भगत ने दी। उन्होंने बताया कि पिछली बरसात में पुलिया बहने के कारण यातायात सुचारू करने को वहां अस्थायी तौर पर वेली ब्रिज बनाया गया था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सीएम पुष्कर धामी ने 21 मीटर स्पान के नए आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ 96 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।विधायक भगत ने कहा कि इस पुल के निर्माण से लोगों के साथ भारी वाहनों के आवागमन में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। साथ ही पर्यटन नगरी नैनीताल आनेजाने वाले पर्यटकों को भी निर्बाध और सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। इसके लिए विधायक ने सीएम धामी का आभार जताया है। इसके अलावा क्षेत्र के विकास को गति देते हुए सीएम ने कालाढूंगी विधानसभा के घुनी नंबर एक, रामणी आनसिंह गीता एनक्लेव फेज 2 और हल्दूपोखरा नायक में कुल 2.2०० किमी लंबे सड़क मार्ग निर्माण के लिए भी 1 करोड़ 76 लाख 4 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।

अल्मोड़ा की अदिति भट्ट ने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन में जीते दो स्वर्ण

अल्मोड़ा(आरएनएस)। लखनऊ में 21 से 28 सितंबर तक आयोजित योनेक्स सनराइज अखिलेश दास मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अल्मोड़ा की अदिति भट्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरे खिताब पर कब्जा जमाया। उन्होंने महिला डबल्स और मिक्स डबल्स दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। महिला डबल्स में महाराष्ट्र की श्रावणी वालेकर के साथ जोड़ी बनाकर खेलते हुए अदिति ने क्वार्टर फाइनल में ओडिशा की ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतप्रणा पांडा की जोड़ी को 7-15, 15-7, 15-8 से हराया। सेमीफाइनल में कर्नाटक की न्यासा करिअप्पा ए और तमिलनाडु की प्रवंधिका राघवन की जोड़ी को 15-11, 15-1० से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में अदिति और श्रावणी की जोड़ी

मरीजों, गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना पीड़ितों को जांच के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग सीएचसी धौलादेवी में तत्काल अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित करने की है। उनका कहना है कि इन सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अस्पताल की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित दस सूत्रीय मांगपत्र भी तैयार किया गया है, जिसे जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। आंदोलन संयोजक डॉ. नीरज पंत ने कहा कि यह पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि जब तक सीएचसी धौलादेवी को आवश्यक सुविधाएं

उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक धरना जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मांगों पर कार्रवाई किए जाने तक धरना जारी रखा जाएगा। ग्राम प्रधानों ने प्रतिदिन आंदोलन में भागीदारी का आश्वासन दिया है। आयोजकों ने क्षेत्र के लोगों से भी धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। धरने में हरीश धर्मवाल, हरीश मलारा, मोहन सिंह भंडारी, बसन जोशी, किशोर जोशी, गोवर्धन पांडे, बसंत पांडे, कैलाश पांडे, डीके जोशी, ईश्वर सिंह, गोकुल भट्ट, गोकुल डसीला, अरुण पटवाल, चंदन सिंह, सुमित शाह, केसर सिंह, ललित वर्मा, सुरेश चंद सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

ऋषिकेश में 357 करोड़ से भूमिगत होगी बिजली की लाइन

ऋषिकेश(आरएनएस)। तीर्थनगरी ऋषिकेश में विद्युत पोल पर दिखने वाले तारों के जाल से अब क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी। इसके लिए क्षेत्र में 357 करोड़ की लागत से परियोजना का शुभारंभ किया गया। जिसमें क्षेत्र में 33 केवी की 48 किमी, 11 केवी की 1०3 किमी तथा एलटी लाइन की 111 किमी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। वीरभद्र मार्ग पर विद्युत विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने भूमि पूजन कर आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने से ऋषिकेश शहर को लंबे समय से दिखाई देने वाले बिजली के तारों के जाल से मुक्ति मिलेगी और शहर की सुंदरता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही विद्युत आपूर्ति अधिक सुचारु एवं निर्बाध बनाने में मदद मिलेगी।

टीबी मुक्त पंचायत बनाने के लिए ग्राम प्रधानों को किया जागरूक

कोटद्वार(आरएनएस)। साझासैण स्थित दुगड्डा ब्लॉक सभागार में टीबी मुक्त पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्राम प्रधानों को टीबी के लक्षणों की पहचान, समय पर जांच और उपचार के साथ ही मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और निक्षय पोषण योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में दुगड्डा ब्लॉक के क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के वरिष्ठ उपचार निरीक्षक कुलदीप सिंह रमोला ने ग्राम प्रधानों को टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर रोगियों की पहचान एवं जांच को प्रोत्साहित करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से गांवों को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को गति मिल सकती है। कार्यक्रम में उमथगांव की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी काकुल वैद्य, प्रधान संगठन के अध्यक्ष सरदार सिंह नेगी, सचिव प्रीतपाल सिंह, ग्राम प्रधान रजनी देवी, अनीता देवी, सरिता देवी, कुमारी रीना, विनोद रावत, ताहिर अली मौजूद रहे।

अल्मोड़ा की अदिति भट्ट ने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन में जीते दो स्वर्ण

ने केरल की नयना एस ओसिस और तमिलनाडु की वार्पिनी विश्वनाथ श्री की जोड़ी को 15-1०, 15-8 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

मिक्स डबल्स में दिल्ली के भव्य छाबड़ा के साथ जोड़ी बनाकर अदिति ने क्वार्टर फाइनल में दिल्ली के दिव्यांश रावत और कर्नाटक की कनिका श्री की जोड़ी को 15-6, 15-14 से हराया। सेमीफाइनल में दिल्ली के वंश देव और मिजोरम की लालरेमपुल की जोड़ी को 15-8, 13-15, 15-13 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में अदिति और भव्य की जोड़ी ने डी. संजय श्रीवास्तव और अध्या वारियथ की जोड़ी को 15-13, 15-9 से हराकर दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अदिति भट्ट द्वाराहाट के धनखोली गांव की रहने वाली हैं और वर्तमान में बेंगलुरु में

प्रशिक्षण ले रही हैं। वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। अदिति की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड बैडमिंटन संघ के चीफ पैट्रन अशोक कुमार, अध्यक्ष डॉ. अलकनंदा अशोक, सचिव बीएस मनकोटी, कोषाध्यक्ष रामावतार अग्रवाल, जिला बैडमिंटन संघ अल्मोड़ा के अध्यक्ष सुरेश कर्नाटक, उपाध्यक्ष गोकुल सिंह मेहता व राकेश जायसवाल, सचिव डॉ. संतोष बिष्ट, उप सचिव संजय नज्जौन, मीडिया प्रभारी डीके जोशी, कोषाध्यक्ष नंदन रावत, अमरनाथ सिंह, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन कोच डीके सेन, लोकेश नेगी सहित बैडमिंटन परिवार, संघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने खुशी जताते हुए अदिति को शुभकामनाएं दीं।

कार शोरूम में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

हमारे संवाददाता

देहरादून। सुभाष नगर स्थित बीएम हुंडई शोरूम में आज सुबह करीब 5 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और शोरूम से उठती आग की लपटों के साथ आसमान में काले धुएं का घना गुबार छा गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। फायर कर्मियों ने पानी की बौछार



कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। फिलहाल आग लगने के कारण और संपत्ति के नुकसान का पूरा आकलन सामने नहीं आया है। आग पर पूरी तरह काबू पाने और मौके के निरीक्षण के बाद ही नुकसान की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा इंतजामों और आपदा से निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहत की बात यह है कि फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है।

श्री आदर्श रामलीला मंचन के लिए रिहर्सल शुरू

संवाददाता

देहरादून। श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट के मंत्री अजय गोयल तथा कोषाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि श्री रामलीला महोत्सव 2026 के मंचन हेतु एक अक्टूबर 2026 से रिहर्सल का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

आज यहां श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट राजपुर देहरादून द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने पारम्परिक स्वरूप में 77 वर्ष में श्री रामलीला महोत्सव -2026 का आयोजन दूसरे नवरात्रि से 12 अक्टूबर 2026 से राजपुर में किया जा रहा है। श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट राजपुर के प्रधान योगेश अग्रवाल ने बताया कि श्री रामलीला महोत्सव राजपुर के मंचन में सभी पात्र स्थानीय हैं, जो दिन रात अभ्यास स्वरूप मेहनत करके अपनी अदाकारी का मंचन करते हैं। ट्रस्ट के संरक्षक विजय जैन ने बताया कि विगत वर्ष आये एक अतिथि के सुझाव पर इस वर्ष श्री रामलीला रंगमंच का आकार काफी बड़ा कर दिया गया। जिसके लिए बड़े परदे और अन्य सामग्री प्रबंधित करनी भी पड़ी।

मंत्री अजय गोयल तथा कोषाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि श्री रामलीला महोत्सव 2026 के मंचन हेतु एक अक्टूबर 2026 से रिहर्सल का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। उपग्रह तन संजीव गर्ग तथा शिवदत्त अग्रवाल ने बताया कि श्रीरामलीला 12 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2026 तक मंचन किया जायेगा।

24 अक्टूबर को कुमार भरत की श्रीराम के वन से वापसी की शोभायात्रा शहंशाह आश्रम से प्रारंभ होकर रात 7-30 बजे ढाकपट्टी राजपुर बस स्टैंड पर पहुंचेगी, जहां श्रीराम भरत मिलन की लीला का हृदयस्पर्शी मंचन किया जायेगा। प्रधान योगेश अग्रवाल ने सभी श्रद्धालू अतिथि गणों और भक्त एवं जनो के राजपुर की मनोहारी श्री रामलीला के दर्शन एवं पुण्य अर्जन हेतु सादर आमंत्रित किया है।

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 3 अक्टूबर को हरिद्वार में

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री और हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ यू.टी. के अध्यक्ष सुमित सिंगला ने बताया कि अग्रवाल समाज के विकास और देश भर में संगठन को मजबूत करने हेतु देश भर के पदाधिकारी 3 अक्टूबर को दो दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने हेतु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सुमित सिंगला ने बताया कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल और राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका के नेतृत्व में हरिद्वार के सप्त ऋषि रोड, मोतीचूर स्थित अखंड दयाधम विचार विमर्श के लिए देश भर से जुड़े पदाधिकारी समाज में होने वाली इस दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश

◆अग्रवाल समाज की भावी पीढ़ी के विकास हेतु विचार विमर्श के लिए देश भर से जुड़े पदाधिकारी
◆समाज के युवा वर्ग में नेतृत्व की भावना को मजबूत करने के लिए होंगे मंथन - सुमित सिंगला

के विभिन्न हिस्सों से 500 के लगभग संगठन पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इस बैठक में अग्रवाल समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मजबूत करने के साथ साथ नई पीढ़ी में नेतृत्व की भावना पैदा करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अग्रवाल संगठन की भावी कार्य योजनाओं जिनमें देश के विभिन्न राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। समाज के युवा वर्ग को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करने और उनके चौमुखी विकास हेतु मंथन किया जायेगा।

बिजली बिलों में टैक्स की भरमार से जनता पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ: कांग्रेस

हमारे संवाददाता

देहरादून। प्रदेश में बिजली व्यवस्था, उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ, अनियमित बिजली कटौती, मलिन बस्तियों में नए बिजली कनेक्शन और विद्युत अवसंरचना से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने यूपीसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने यूपीसीएल से उपभोक्ताओं की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के साथ ही बिजली बिलों में लगाए जा रहे विभिन्न शुल्कों एवं अधिभार की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की।

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि आम उपभोक्ता पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में बिजली की मूल खपत के अतिरिक्त विभिन्न शुल्क और अधिभार लगाए जाने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध बिजली बिल की प्रति में 8,974.50 रुपये की बिजली लागत के साथ 550 रुपये फिक्स्ड चार्ज, 220 डिमांड चार्ज, 173.70 विद्युत कर, 115.80 हरित ऊर्जा उपकर और 860.23 एफपीपीसीए अधिभार दर्ज है। बिल में वर्तमान योग 10,692.



23 दर्शाया गया है तथा 176 की अतिरिक्त प्रतिभूति किस्त के बाद कुल देय राशि 10,868 रुपये है। लालचंद शर्मा ने कहा कि यूपीसीएल को स्पष्ट करना चाहिए कि बिजली की मूल खपत के अतिरिक्त अलग-अलग मदों में लगाए जा रहे शुल्क और अधिभार किस आधार पर वसूले जा रहे हैं। उपभोक्ता को बिल में प्रत्येक शुल्क की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए और अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर ट्रांसफार्मर, जर्जर विद्युत लाइन, अर्थिंग और शिकायत निवारण जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं से विभिन्न मदों में अतिरिक्त भुगतान लिया जा रहा है। उन्होंने यूपीसीएल से बिलिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की मांग की।

पूर्व विधायक राजकुमार ने देहरादून की मलिन बस्तियों में नए बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई बस्तियों में परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं और उनके पास बिजली-पानी के बिल सहित विभिन्न सरकारी दस्तावेज भी उपलब्ध हैं, इसके बावजूद नए बिजली कनेक्शन के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजकुमार ने कहा कि सरकार और ऊर्जा निगम को गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बार-बार होने वाली बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अनियोजित कटौती के कारण आम लोगों, विद्यार्थियों, दुकानदारों और कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

चार सूत्रीय मांगों को लेकर एलटी अभ्यर्थियों ने किया सचिवालय कूच



संवाददाता

देहरादून। चार सूत्री मांगों को लेकर एलटी अभ्यर्थियों ने सचिवालय कूच

कर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।

आज यहां एलटी अभ्यर्थी परेड ग्राउंड

में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने सचिवालय के लिए कूच किया। जब वह सचिवालय के करीब पहुंचे तो पुलिस ने उनको बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक हुई। जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गये। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे जिनके माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। उनका कहना था कि जहां रिक्त पदों न हो वहां उच्च न्यायालय के के आदेश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया की जाये। उन्होंने कहा कि यूकेएसएसएससी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची जारी की जाये। उनका कहना था कि 585 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाये जो पिछले दो वर्षों से मानसिक पीडा झेल रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों ने किया जिलाधिकारी का अभिनंदन

संवाददाता

देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की पूर्व बेला पर वरिष्ठ नागरिकों ने जिला स्तरीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के गठन पर खुशी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी का अभिनंदन किया। संयुक्त नागरिक संगठन का एक शिष्टमंडल

जिला स्तरीय समिति के गठन पर जताई खुशी

संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल बी.एम. थापा के नेतृत्व में गुलाब के फूल लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा।

वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा अपने वायदे के अनुरूप जनपद स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समिति का गठन कराया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समिति पीड़ित, असहाय और जरूरतमंद बुजुर्गों



की समस्याओं के निराकरण में प्रभावी भूमिका निभाएगी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए प्राथमिकता के आधार पर हरसंभव सहयोग देने के लिए तत्पर है। उन्होंने जीवन के नवें दशक की सीमा पार कर रहे कर्नल बी.एम. थापा और प्रकाश नागिया को शाल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में गिरीश चंद्र भट्ट, सुलोचना भट्ट, उमेश सक्सेना, राधा तिवारी, जगदीश बावला, डॉ. टी.एन. जोहर, एस.पी. चौहान, दिनेश भंडारी, ठाकुर शेर सिंह, दिनेश सक्सेना, उमेश्वर सिंह रावत, प्रदीप कुकरेती, अवधेश शर्मा, मुकेश नारायण शर्मा, कुसुम दशमाना, संजय गर्ग, मेजर एम.एस. रावत, मोहन सिंह खत्री, जगदीश भंडारी, अवधेश पंत सहित अनेक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने की यूआईआईडीबी के प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा

◆शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर के कार्यों में धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

संवाददाता
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने यूआईआईडीबी के प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर के कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की।

आज यहां मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में उत्तराखण्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) की एजीक्यूटिव कमेटी की बैठक में विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण करने तथा परियोजनाओं की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीडीसीसी द्वारा लगभग दस माह में मात्र 10 प्रतिशत प्रगति किए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए परियोजना के लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर की तैनाती कार्यस्थल पर ही सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग हो और मौके पर आने वाली



समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यूआईआईडीबी के सभी प्रोजेक्ट्स की निर्धारित टाइमलाइन के साथ पर्ट चार्ट तैयार किया जाए और प्रत्येक बैठक में इसके अनुरूप परियोजनावार प्रगति प्रस्तुत की जाए।

उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में निर्धारित समय के अनुरूप प्रगति नहीं हो रही है, उनमें कारणों की स्पष्ट पहचान करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव नियोजन को भी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने रिवर राफ्टिंग डेवलपमेंट से सम्बन्धित कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं

के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए यूपीडीसीसी को अगले पांच वर्षों के लिए अपनी समर्पित टीम विकसित करते हुए कार्यस्थल पर तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एवं ऋषिकेश क्षेत्र के लिए अलग यूनिट की व्यवस्था की जाए, ताकि परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में किसी प्रकार की समस्या न हो। मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ मेला 2027 को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले कार्यों को निर्धारित समयसीमा में हर हाल में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने सती कुंड से सम्बन्धित कार्यों को 15 दिसंबर तक पूर्ण करने के लिए श्रमिकों एवं शिफ्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गति बढ़ाने के साथ ही गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हरिद्वार में कराए जा रहे कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के महाप्रबंधक हरिद्वार में ही तैनात रहकर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और परियोजनाओं की प्रगति की पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त को उपलब्ध कराएंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश भी दिए।

रात घर में घुसा चोर 36 मिनट तक घर खंगाला!

हमारे संवाददाता
देहरादून। ऋषिकेश में चोरी की एक घटना ने रात की सुरक्षा और पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य दयाशंकर पांडे के घर में देर रात एक चोर घुस गया और करीब 36 मिनट तक घर के भीतर अलग-अलग कमरों में घूमता रहा। घटना के दौरान घर में बुजुर्ग महिला भी मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि चोर रात करीब 2.45 बजे घर में दाखिल हुआ और लगभग 3.21 बजे बाहर निकला। इस दौरान उसने घर के कई हिस्सों की तलाशी ली। सीसीटीवी फुटेज में भी संदिग्ध के घर में आने-जाने की गतिविधियां सामने आने की बात कही जा रही है। दयाशंकर पांडे के अनुसार, चोर उस कमरे तक भी पहुंचा, जहां उनकी बुजुर्ग माता सो रही थीं। बताया गया कि चोर करीब 10 मिनट तक उस कमरे में मौजूद रहा। उनकी माता के गले में सोने की चेन और हाथ में कंगन थे। ऐसे में यदि चोर ने कोई हिंसक कदम उठाया होता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। घटना के बाद दयाशंकर पांडे ने क्षेत्र में रात के समय होने वाली पुलिस गश्त को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि नियमित और प्रभावी गश्त होती तो संभव है कि चोर घर में प्रवेश करने से पहले ही सतर्क हो जाता। फिलहाल घर से एक भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर चोरी होने की जानकारी सामने आई है। घर में रखे अन्य सामान की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही चोरी गए सामान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर उसे पकड़ने की चुनौती है।



डंपर व स्कूटी में हुई टक्कर, बेटी की मौत पिता घायल

हमारे संवाददाता
नैनीताल। हल्द्वानी-बरेली हाईवे पर हल्दूचौड़ में गायत्री कुंज के पास डंपर और स्कूटी की टक्कर में 14 वर्षीय किशोरी व उसके पिता घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजा गया। उपचार के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया, जबकि उसके पिता का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 11.35 बजे हाईवे पर एचपी पेट्रोल पंप के सामने सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। स्कूटी पर किच्छा के बंडिया खाद गोदाम नहर के पास निवासी करीब 42 वर्षीय सुरेंद्र कुमार पुत्र हेतराम और उनकी करीब 14 वर्षीय बेटी प्रेरणा सवार थीं। दोनों हादसे में घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी भेजा। उपचार के दौरान किशोरी प्रेरणा की मौत हो गई। वहीं, उसके पिता सुरेंद्र कुमार का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में शामिल डंपर को पुलिस ने मौके से कब्जे में ले लिया। दोनों वाहनों को चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है।

आज से 62 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर!

संवाददाता
नई दिल्ली। त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले आम जनता और कारोबारियों की जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है, जिससे खासकर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि के बाद अब कमर्शियल सिलेंडर 2815 रुपये में मिलेगा। छोटे गैस उपभोक्ताओं और दुकानदारों के काम आने वाले 5 किलोग्राम वाले कमर्शियल/छोटू सिलेंडर के दाम में भी 15.50 रुपये की



बढ़ोतरी की गई है। अब यह सिलेंडर 781 रुपये में उपलब्ध होगा। दामों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और कैटरिंग का काम करने वाले कारोबारियों के बजट पर पड़ेगा, जो पहले से ही त्योहारों के सीजन में व्यस्त हैं।

गैस उपभोक्ताओं के लिए एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। नियमों के

तहत आज से बिना बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के गैस सब्सिडी का लाभ मिलना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, उन्हें सब्सिडी का लाभ पाने के लिए जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में अप्रैल में भी बढ़ोतरी की गई थी। पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज के रास्ते एनर्जी की सप्लाई में आ रही रुकावटों को देखते हुए उस दौरान सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 195.50 से 214 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद मई में भी रेट बढ़ाए गए। इस दौरान एक ही झटके में कीमतें 993 प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दी गई थीं। फिर जून में भी 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।

फिर नीट-यूजी पर सियासी घमासान

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखण्ड में नीट-यूजी काउंसलिंग के दौरान प्रमाणपत्रों की सत्यता को लेकर सामने आए मामलों ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर मुद्दे को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया।

दरअसल, नीट-यूजी 2026 की राज्य काउंसलिंग में फर्जी अथवा संदिग्ध प्रमाणपत्रों के आधार पर मेडिकल सीट हासिल करने के मामले सामने आने के बाद जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हाल में 12 और अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने पर उनके सीट आवंटन निरस्त किए गए। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन प्रक्रिया आगे

भी जारी रहेगी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली और प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आरोपों के जवाब में चमोली ने कहा कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरी व्यवस्था को कटथरे में खड़ा करने से पहले तथ्यों को सामने रखना जरूरी है।

भाजपा का तर्क है कि सरकार ने शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि मामले सामने आते ही जांच के निर्देश दिए और प्रमाणपत्रों के सत्यापन का दायरा बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी आरक्षित श्रेणियों से जुड़े

प्रमाणपत्रों की जांच के निर्देश दिए थे। शुरुआती जांच में प्रमाणपत्र निरस्त करने के साथ प्रवेश भी रद्द किए गए हैं। चमोली के पलटवार का राजनीतिक संदेश साफ है कि भाजपा इस पूरे प्रकरण को व्यवस्था में सामने आई गड़बड़ी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर सवाल उठा रही है।

मामले ने इसलिए भी गंभीरता बढ़ा दी है क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों तक सीमित नहीं है। जांच अब इस बात तक पहुंच रही है कि प्रमाणपत्र जारी करने से लेकर काउंसलिंग में उनके सत्यापन तक कहीं प्रक्रियागत

◆विधायक विनोद चमोली ने यशपाल आर्य के आरोपों पर किया पलटवार
◆भाजपा विधायक बोले व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले तथ्य सामने रखें
◆बोले-प्रदेश सरकार ने शिकायत मिलते ही जांच का दायरा भी बढ़ा दिया

आर.एन.आई.- 59626/94
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटेर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808
नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटेर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।